संसद में बहस

l pkj vkj l puk ik|kfxdh e=ky;
d dk;dj.k ij ppk

शहर और गांव के बीच 'डिजिटल विभेद' पैदा कर रही संप्रग सरकार

• iHkkr >k

Hkkjrh; turk ikVh

प्रकाशकीय

संप्रग सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत बजट 2009–10 के अंतर्गत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यकरण पर 23 जुलाई, 2009 को राज्यसभा में चर्चा हुई। चर्चा प्रारम्भ करते हुए श्री प्रभात झा ने अपने तर्कों एवं तथ्यों के सहारे केन्द्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। श्री झा ने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार ने बजट में सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि सरकार दूरसंचार विकास हेतु शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी कर एक डिजिटल विभेद पैदा कर रही है।

हम इस पुस्तिका में श्री प्रभात झा के भाषण का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं।

çdk'kd
Hkkjrh; turk ikVh
11] v'kksd jkM]
ub fnYyh&110001

tqykb] 2009

शहर और गांव के बीच 'डिजिटल विभेद' पैदा कर रही संप्रग सरकार

& iHkkr >k

उपसभापति महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में अपनी चर्चा को आरम्भ कर रहा हूं। बुनियादी तौर पर मनुष्य का स्वभाव जिज्ञासु होता है। वह जानना चाहता है, वह सुनता है, देखता है और महसूस करता है और उसके बारे में जानने की कोशिश भी करता है। जाने–पहचाने दो दिल, चाहे पास रहें या दूर, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वे एक–दूसरे के बारे में न जानना चाहते हों।

यही कारण है जिसकी वजह से आदिकाल से संचार व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। विभिन्न युगों में इसकी व्यवस्थाएं अलग–अलग रही होंगी, लेकिन संचार कभी रुका नहीं है। जब मानव पढ़ा–लिखा नहीं था, तब वह मोम से, लकड़ी से, नुकीले लोहे से, पत्थर की नोंक से अपनी बातें लिखता था और संवाद करता था। पेरू में जो स्पैनिश लोग होते हैं, वे गांठदार रस्सी से कितनी गांठें बंधी हैं, उसके द्वारा संदेश भेजते थे और जिसको संदेश मिलता था, वह समझता था कि इन गांठों का क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार प्राचीन काल में जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय हरकारा राज्यों में दौड़ा दिए जाते थे। उसके साथ वह घोड़े पर चढ़कर जाता था और साथ में नुकीला भाला होता था। उस भाले पर मशाल जलती थी और रस्सी लटकी रहती थी। इसका मतलब यह होता था कि जो लोग युद्ध में भाग नहीं लेंगे, उनका घर जला दिया जाएगा, जो लोग लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।

महोदय, अब मैं डाक विभाग पर आता हूं। 1836 में पहली बार रोलैंड हिल ने डाक व्यवस्था का सर्वेक्षण किया। आखिर डाक भारत की जिंदगी क्यों है, यह विभाग क्यों है, उसका एक उदाहरण है। 1836 में रोलैंड हिल ने जब सर्वेक्षण किया तो उसने कहा कि जितनी दूरी पर डाक जाती है, उस

दूरी के हिसाब से पैसा नहीं लेना चाहिए। उसने सर्वेक्षण पर रिपोर्ट दी कि पैसा पत्र के वजन के आधार पर लेना चाहिए। उसी समय से जितना पत्र का वजन होता है, उतना पैसा लगने लगा। इससे जाहिर होता है कि संचार जो है, जो डाकतार है, यह सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत का एक समर्थ साधन है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस विभाग की महत्ता सिर्फ मंत्रालय के नाते नहीं है, विभाग के नाते नहीं है। डाक गांव में एक परिवार के रूप में काम करता है। मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा – पांच मिनट के लिए आप अपने गांव की तरफ चले जाएं या शहर के किसी इलाके में चले जाएं – वह डाकघर, वह डाक बाबू, वह डाकिया, उसकी साइकिल, उसकी खाकी पैंट, खाकी कुरता, खाकी शर्ट, लाल धारी वाली टोपी, उसकी घंटी की आवाज सुनते ही आंगन से दौड़ता हुआ बच्चा बाहर आता है और कहता है, डाकिया काका, क्या लाए हो? वह कहता है कि यह चिट्ठी लाया हूं। उस गांव का डाकिया कोई नौकर नहीं हुआ करता था, डाकिया वहां पर कोई employee नहीं था, वह उस पंचायत का, उस गांव का, अपने इलाके का एक संदेशवाहक होता था, परिवार का सदस्य होता था। कोई उसे काका कहता था, कोई उसे मामा कहता था और कोई उसे चाचा कहता था। इतने बड़े परिवार में, आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई निरक्षर होता था तो डाकिया उसकी चिट्ठी स्वयं पढ़ता था। अगर तार पर कोई दुखद समाचार होता था तो उसके हाथ कांपते थे कि मैं कैसे चाची को बताऊं कि परदेस में उसका जो रिश्तेदार रहता है, वह expire हो गया है। वह बताने में समर्थ नहीं होता था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े डाक विभाग में 6 लाख लोग काम करते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि डाक विभाग संस्कृति और परम्परा का हिस्सा हुआ करता था। आप सब कल्पना कर रहे होंगे तो आपको भी ऐसा ही लगा होगा। आज किसी बच्चे से पूछिए कि डाकिया क्या होता है, कौन है? वह कहेगा कालिया का भाई है। उसको पता ही नहीं है कि डाकिया क्या होता है। हमने एक संस्कृति को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। इस विभाग में लगभग 6 लाख लोग काम करते हैं और इसमें नियमित कर्मचारियों के

डाकतार सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत का एक समर्थ साधन है।

अलावा ग्रामीण डाक सेवकों की लाखों में संख्या है। उपसभापति महोदय, इस ओर जब देखते हैं तो भारत में एक लाख पचपन हजार पैंतिस डाकघर हैं। यह 2008 की रिपोर्ट में है। इसमें एक लाख उन्तालिस हजार एक सौ तिहत्तर ग्रामीण डाकघर हैं 15,862 शहरी डाकघर हैं। जरा इन डाकघरों की स्थिति तो जाकर देखिए। अभी जैसे बरसात हुई तो वहां पानी टपकेगा। तो डाकघर की स्थिति क्या है? यह लाखों–करोड़ों रूपया आपको देता है, लेकिन उन डाकघरों की स्थिति देखकर आपको अजीब लगेगा। मैंने एक डाकघर में जाकर पूछा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आपके यहां क्या–क्या हुआ है? उसने बताया कि कभी–कभी पुताई हो जाती है, कभी–कभी रंगाई हो जाती है, यही हमारा मॉडर्नाइजेशन है। हम भारत को किस युग में ले जाना चाहते हैं? मैंने वहां एक और चीज देखी। हमने जो आधुनिकतम संचार व्यवस्था में मोबाइल वगैरह शुरू की है, तो इस संदर्भ में हमने सोचा कि चिट्ठियां बहुत कम जाती होंगी। मैंने इसकी भी जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि वोल्यूम और क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आई है, चिट्ठियां उतनी ही आ रही हैं, अन्तर इतना हुआ है कि पर्सनल चिट्ठियां बंद हो गई हैं, बिजनेस की चिट्ठियां ज्यादा आने लगी हैं, लेकिन चिट्ठियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। चिट्ठियां निरन्तर जा रही हैं, उसका स्वरूप बदल गया होगा, स्पीड पोस्ट से जाने लगा होगा, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई है। आप लोगों को लगता है कि डाक का काम बंद हो गया है। सरकार का जो मंत्रालय है, वह भी लगभग उसी दिशा में चल रहा है, वह अन्य चीजों में जाने लगा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सन् 1984 से इस डाक तार विभाग में एक भी नियुक्ति नहीं है, इक्का–दुक्का हुई हो, तो हो सकती है, लेकिन 1984 के बाद कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है। अब देश की जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है? लेकिन आप देखेंगे कि डाकघर में नियुक्ति नहीं हुई है, डाकियों की संख्या नहीं बढ़ी है, डाक बाबू की संख्या नहीं बढ़ी है, जनसंख्या भले ही बढ़ गई हो, काम उतना ही है, इससे सारे लोग परेशान हैं। अब यहां पर एक और विडम्बना देखिए। इस विभाग में अगर कोई अनुकम्पा नियुक्ति होती है –मरसी अपोइंटमेंट, तो यह सदन सुनकर आश्चर्य करेगा कि सौ डाक परिवारों में अगर कोई मृत्यु होती है, तो यह सरकार, यह मंत्रालय पांच लोगों को ही नौकरी देता है। यहां पर पांच परसेंट मरसी अपोइंटमेंट है। तो उन 95 परसेंट लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? क्या अन्याय किया है उन्होंने? फिर यह पांच परसेंट

अपोइंटमेंट किसकी मरसी पर होगा? कौन देगा इनको नौकरी, इसका क्या क्राइटेरिया है? मुझे लगता है कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु हो जाए, तो अनुकम्पा की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ये मानकर ही नहीं चलते कि वे कोई हमारे कर्मचारी हैं। महोदय, आपने देखा होगा कि पहले रेलगाड़ी में एक लाल डिब्बा हुआ करता था। उस पर लिखा होता था –'डाक तार विभाग।' उस डिब्बे में चिट्ठियां बोरी की बोरी रहती थीं तथा पूरी बोगी में लोग छंटाई करते थे। डाकिये उसमें जाते थे, छंटाई कर चिट्ठियां अलग कर देते थे। लेकिन अब यह देखिए कि रेलगाड़ी में वह डिब्बा बन्द हो गया है तथा कुछ बोरी चिट्ठियां रखने के लिए छोटा सा स्पेस दे दिया गया है और उस स्पेस में चिट्ठियां रहती हैं, परन्तु उनकी छंटाई नहीं होती है। इसीलिए आज आपकी चिट्ठी दो दिन में नहीं पहुंचती है वह चार दिन में, पांच दिन में, दस दिन में पहुंच रही है। उसका बहुत बड़ा कारण है छंटाई न होना। 1986 से छंटाई होना ही बंद हो गया और जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उनके बदले में किसी को नहीं रखा जा रहा है। डाक विभाग में एक आर0एम0एस0 यानी शौर्टिंग ऑफिस छंटाई यह सब विभाग हुआ करता था। वह पूरी तरह से बंद है।

स्पीड पोस्ट की भी हालत खराब है। मुझे डाकतार विभाग के लोगों ने ही बताया, कि भारत में जो प्राईवेट कूरियर सेवा है, यह डाकतार विभाग के अधिकारियों द्वारा बेनामी रूप से उनके द्वारा चलाई जाती है। 27 परसेंट डाक कूरियर से प्रभावित है।

एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि संचार और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय के एक विभाग का काम आज भी मैनुअल हो रहा है। स्पीड पोस्ट के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन इसकी भी हालत खराब है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य लगा, और यह मुझे डाकतार विभाग के लोगों ने ही बताया, कि भारत में जो प्राईवेट कूरियर सेवा है, यह डाकतार विभाग के अधिकारियों द्वारा बेनामी रूप से उनके द्वारा चलाई जाती है। 27 परसेंट डाक कूरियर से प्रभावित है। अब एक ताजा उदाहरण देख लीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर डाक विभाग का TMS office है। वहां कर्मचारियों की बहुत कमी होने के कारण ओवर टाइम करना पड़ता है। वहां के एक कर्मचारी ने मुझे बताया

कि साहब, अगर हम काम से एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तो डायजनॉल पनिशमेंट मिलती है। जब मैंने डायजनॉल नाम सुना, तो मुझे लगा कि वह किसी दवाई का नाम बता रहा है। यहां डायजनॉल का मतलब दवाई से नहीं है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अगर वह कर्मचारी एक दिन की छुट्टी लेता है, तो उसको ओवर टाइम भी नहीं मिलता है और जो उसने एक दिन पहले काम किया था, उसका भी पैसा काट लिया जाता है। यह इस डाकतार विभाग की कहानी है। सर, मैं यहां संचार मंत्रालय के डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण सेवकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वे तीन से पांच घंटे तक काम करते हैं। पहले इन्हें ई.डी.पी. कहा जाता था, इन्हें काम नियमित कर्मचारियों की तरह से करना पड़ता है, लेकिन इनकी तरफ कोई नहीं देखता है, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इनकी पेंशन नहीं है, ग्रेच्युविटी नहीं है, कोई चीज़ इनके लिए नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा गया और EDA को उन्होंने सिविल पोस्ट माना। उन्होंने कहा – They are the civil servant. लेकिन उसके बाद भी डाकतार विभाग कहता है कि हम ग्लोबल सर्विस सेंटर्स खोलने वाले हैं। आप इनको खोलिए, लेकिन आपके जो भारत में सेंटर्स हैं, पहले उनकी हालत सुधारिए। मेरा इतना ही निवेदन है। डाकतार विभाग के लिए वर्ष 2009–10 में 6021.26 करोड़ रुपये की मांग रखी गई थी। इस विभाग में 2008–09 के लिए संशोधित बजट 4228.78 करोड़ का था। आपने बजट को कुछ बढ़ाया है, लेकिन आपने परिवहन में क्या किया है आपने परिवहन का बजट कम कर दिया है। गांव में जो गाड़ियां चिट्ठी लेकर जाती थीं, उनके लिए आपने बजट कम कर दिया है। आप किसी भी मुख्य पोस्ट ऑफिस में जाइए, आपने सेविंग वाले मामले में क्या किया है ? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि चिट्ठी बांटने वाले से कहा जा रहा है कि सिनेमा के टिकट बेचो, रेल के टिकट बेचो, नरेगा में लगो। नरेगा में पूरे पोस्ट ऑफिस के लोग काम करते हैं। आपने क्या कर दिया है? आप एक संस्कृति को पूरी तरह से बदलने में लगे हुए हैं। कैश सर्टिफिकेट के काम में काफी लापरवाही बरती जा रही है, यहां करोड़ों का घपला और भ्रष्टाचार जारी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह 2006–07 की सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है। उन्होंने कहा है कि आप यहां ध्यान दीजिए। यहां करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इस तरफ आगाह करने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। आज़ादी के 62 वर्ष बाद भी एक संस्कृति और परम्परा से जुड़े इस विभाग की बहुत ही दयनीय हालत है। मैं आपको बताना चाहता

हूं कि यह विभाग कितना मजबूत विभाग है। वर्ष 2003–04 में प्रीमियम सेवाओं की अतिरिक्त अधिकृत आय 425.74 करोड़ रूपये थे, आज 2008–09 में यह बढ़कर 2141 करोड़ रुपये हो गयी है। आपकी स्पीड पोस्ट की कमाई बढ़ गई है। नरेगा के दो करोड़ खाते आपके पास हैं, लेकिन न आपका डाकघर ठीक है, न आपके डाकिए की हालत ठीक है, न आपके डाकबाबू की हालत ठीक है, न डाक विभाग के ग्राम सेवकों की हालत ठीक है। आप इसके लिए क्या करेंगे? इतना ही नहीं है, कुछ यूनियन्स हैं, उन सभी यूनियनों को एक समान दर्जा दिया जाना चाहिए, आपके द्वारा वह भी नहीं दिया जा रहा है। डाककर्मियों के सभी वर्गों के लिए ए.सी.पी. योजना लागू होनी चाहिए, वह भी लागू नहीं हो रही है। आउटसोर्सिंग समाप्त होना चाहिए, वह भी नहीं हो रही है। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन लिखित शिकायतों के बावजूद पता नहीं आपका मंत्रालय ढ़या कर रहा है ? महोदय, यह तो थी डाकतार विभाग की कहानी। अब आ जाइए सूचना प्रौद्योगिकी पर। मैं आपको सुना रहा हूं जुलाई, 2009 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 2008 तक आईटी सुपर पावर बनाने का दावा हो रहा है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यह अद्भुत लाईन है। यह मेरा कहा हुआ नहीं है। यह वेब साइट पर है। जुलाई 2009 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत को 2008 तक आईटी सुपर पावर बनाने का दावा कर रही है। Department of Information Technology की वेब साइट पर मंत्रालय का विज़न लिखा है । "to make India an IT super-power by the year 2008." इसका रेफ्रेंस भी है, जब स्वयं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट अपडेटेड न हो, तो यह मंत्रालय किस प्रकार की सूचना क्रांति इस देश में लाएगा, आप इसका अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। भारत को सन् 2008 तक IT Super Powes बनाने की बात कही जा रही है। यह 2009 का जुलाई का महीना चल रहा है और सन् 2008 को बीते सात महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपका वही विजन है और वही बात इस पर चल

जब स्वयं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट अपडेटेड न हो, तो यह मंत्रालय किस प्रकार की सूचना क्रांति इस देश में लाएगा, आप इसका अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं।

रही है। महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में बता रहा हूं। इस UPA की सरकार के सत्ता में आने के बाद इस सदन में तीन डाक्युमेंटस आए हैं। राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण में कहा गया है कि अगले तीन वर्षों में अपनी पंचायतों में भारत निर्माण सेवा केन्द्रों के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक शासन व्यवस्था होगी। मैंने आज तक यह नहीं सुना है कि कौन सी इलैक्ट्रोनिक शासन व्यवस्था है। मैंने ई–गवर्नेंस तो सुना था, लेकिन इलैक्ट्रोनिक शासन व्यवस्था, आदमी नहीं होगी, इलैक्ट्रोनिक वस्तुएं काम करेंगी। इसके सिवाय अभिभाषण में एक भी बात Information Technology के बारे में नहीं कही गई है। जब कि आप इसको इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा इकोनोमिक सर्वे है। आपने इकोनोमिक सर्वे में भी इन्टरनेट की बात की है, ब्रॉडबैंड की बात की, बाकी किसी चीज की बात नहीं है। और छोड़िए, जो आपका बजट पत्र है, उसमें भी आपने क्या किया है, इसमें क्या किया है, इसमें Information Technology, सूचना प्रौद्योगिकी कोई शब्द नहीं है। आप कैसे 21वीं सदी में जाएंगे और कैसे सुपर पावर बनाएंगे? यह आपका डाक्युमेंट है, मेरा नहीं है। महोदय अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 5666 टावर लगाए गए हैं। मैं आपको 21वीं सदी के भारत की ओर ले जा रहा हूं। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में इन टावरों की संख्या 4 लाख से ऊपर है। हर महीने शहर में 10 हजार से अधिक टावर लगाए जाते हैं, लेकिन एक–दो साल बीतने के बाद गांवों में 10 से 15 हजार टावर लगाए जाते हैं। आप देखिए कि गांवों में कम टावर लग रहे हैं, लेकिन आप पैसा किससे ले रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार विकास हेतु 5 परसेंट लेवी जो USO universal service obligation के अंतर्गत संग्रहित की जाती है, उसका 30 परसेंट भी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च नहीं कर पाई है। महोदय, इससे भारत के अंदर एक digital divide पैदा हो रहा है। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच एक गहरी खाई बैठती जा रही है। इसका यह परिणाम हो रहा है कि आज हम कितनी बातें करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम पाकिस्तान से भी इन्टरनेट यूज़ में बहुत पीछे हैं। इन्टरनेशनल टेलीकॉम्युनिकेशन यूनियन के अंतर्गत Nilson online अध्ययन के अनुसार कहता है कि जहां भारत में जनसंख्या का 7.14 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करता है, वहीं पाकिस्तान में 10.01 प्रतिशत है और चीन में 22.4 फीसदी इंटरनेट का प्रयोग होता है। आखिर ग्रामीण लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? भारत के गांवों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप इस तरह का क्यों भेदभाव करते है? आपको इसके लिए

प्रयास करना होगा कि गांवों का भेद मिटे और आपका मंत्रालय गांवों के साथ भेदभाव न करे। आप इन बेसिक चीजों पर नहीं जाते हैं। उपसभापति महोदय, मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो कुछ भी होता है, सब जोश खरोश में हो जाता है। पहले निर्णय फिर घोषणा होती है और इम्पलीमेंट के जितने तरीके हैं, उनमें यह नहीं देखा जाता है कि यह होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। मैं मुम्बई में पढ़ता था और यह सन् 1964 की बात है। मैं 1964 में अपनी बहन की शादी में बिहार गया था। मैं मुम्बई जैसे शहर से गांव में गया था और मैंने वहां देखा कि सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने अपने बाबा से पूछा कि बाबा आपके गांव में बिजली क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि देखो यह बिजली का पोल आ गया है और उन्होंने मेरे मुंह में गुड़ का ढ़ेला डाल दिया तथा कहा कि चुप रहो। उन बातों को दो साल बीत गए और सन् 1966 का वर्ष आया तथा मेरे बाबा नहीं रहे। मेरे पिता जी उस उम्र में पहुंचे और मैं भी थोड़ा बड़ा हुआ। मैंने पिता जी से कहा कि अभी तक वह बिजली नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है तो तालाब में, पोखर में जाकर नहा आओ, लेकिन ज्यादा बोलो मत और मैं चुप हो गया। महोदय, इसके बाद थोड़ा और आगे चलें, सन् 1993 में मेरे पिता जी की भी मृत्यु हो जाती है तो मेरा पांच साल का बेटा मराठी संस्कृति से है, वह मुझसे पूछता है कि बाबा तुम्हारे गांव में लाइट नहीं है? मैंने कहा कि फिर बेटा हम क्या करें? हमने कहा कि हमारे पिता जी के पिता जी ने बिजली नहीं देखी। मेरे पिता जी के पिता जी ने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। मेरे पिताजी ने नहीं देखी, मैं तेरा पिता हूं, मैंने नहीं देखी, पता नहीं तेरी शादी के बाद जब तू पिता बनेगा तो बिजली देखेगा कि नहीं देखेगा। हम इस युग में कम्प्यूटर की बात कर रहे हैं। साठ हजार गांवों में बिजली नहीं है, आप कम्प्यूटर कहां लगाओगे? मैं आधुनिकतम चीजों का, मॉडर्नाजाइजेशन का विरोधी नहीं हूं, खूब संचार कीजिए, लेकिन आप पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर तो तय कर लीजिए। आप यह सब नहीं कर रहे हैं। इसका बेसिक कारण क्या है, हमारे देश में कम्प्यूटर का उपयोग क्यों नहीं बढ़ रहा है, कम्प्यूटर के प्रति

हमने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की प्रभावी उपस्थिति दिखा सकें।

लगाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? कारण यह है कि भाषाओं के ऊपर हमने कोई प्रयत्न ही नहीं किया है। हमारी भाषा हिंदी है, अंग्रेजी के माध्यम से चलना चाहिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की प्रभावी उपस्थिति दिखा सकें। चीन में भारत से अधिक लोग अंग्रेजी समझते और बोलते नहीं हैं, उनकी अपनी भाषा है। वे अपनी भाषा के आधार पर देखते हैं और आज भी वहां हम से तीन गुणा लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। भारत में हम इंटरनेट और दूरसंचार के साधनों के माध्यम से अगर अंग्रेजी को बाहर करने की सोचें तो सब डंप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम इस तरफ प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? हमारा मंत्रालय इस तरफ क्यों नहीं देखना चाहता है? हम छोटे–छोटे गांवों में पहुंचना चाहते हैं, तो हमें भाषा का सहारा लेना होगा। भाषा तकनीक के विकास के लिए आप इस विभाग की मजेदार कहानी देखिए कि भाषा के विकास के लिए या तकनीकी डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा पिछले वर्ष रखा गया था, उतना ही पैसा इस बार रखा गया है। आपकी किसमें रुचि है? आप विकास करना नहीं चाहते हैं। आपने अपना 2600 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। आपने कहा सूचना प्रौद्योगिकी बजट में पिछले वर्ष 7.89 करोड़ की राशि थी, उतनी ही राशि आपने इस वर्ष भी तकनीकी विस्तार के लिए रख दी है। आगे आइए – जनता के लिए सूचना प्रौद्यागिकी के लिए 6 करोड़ रुपए थे, इस बार भी 6 करोड़ रुपए हैं। यह आखिर है क्या? आप क्यों महिला अनुसूचित–जाति, अनुसूचित–जनजाति पर अन्याय करना चाहते हैं? क्या आप वहां तक आई.टी. को पहुंचाना नहीं चाहते हैं? क्या इन चीजों को गांव से महरूम रखना चाहते हैं? यह आपको देखना पड़ेगा। मैं आपके अच्छे निर्णयों का स्वागत भी करना चाहता हूं। आपने कहा है, बिहार में घोषणा भी की है, दस पैसे प्रति मिनट पर टेलीफोन कॉल्स की बात कही थी, लेकिन देखकर आश्चर्य होगा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपने घोषणा की है, यह अच्छी बात है, लेकिन आप इसको पूरा कीजिए। मैं आपसे इसके आगे कहूंगा कि अगर दस पैसे प्रति कॉल के हिसाब से आप लेते हैं तो उसी रेट से, काफी कम रेट पर गांव के लोगों को इंटरनेट भी उपलब्ध हो सकता है। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एम.एन.पी) की घोषणा तो आपने कर दी, लेकिन यह कहां है? आपका यह एम.एन.पी. कहां चला गया? वाइस ओवर इंटरनल प्रोटोकॉल पर आज तक आपने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है, जबकि इसे उठाए बिना आप गांव में जा नहीं

सकते हैं। आज विदेशी कंपनियां भारत में वी.ओ.आई.पी. धड़ल्ले से बेच रही है, परंतु भारत में कुछ निहित स्वार्थों को संरक्षित करने के लिए इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। जहां आपकी अनेक योजनाओं की बात है, आप घोषणा करते रहिए, सब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। दूसरी ओर आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल., जो नवरत्न कंपनियों में गिनी जाती हैं, आज अपना बाजार प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथों में खोती जा रही हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स को मंत्रालय ने अनावश्यक और अनैतिक छूट दे रखी है, जबकि एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. को इनके साथ नियमों के अधीन प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है। अब आप देखिए कि प्राइवेट ऑपरेटर्स 128 केबीपीएस स्पीड को ब्रॉड बैंड कहकर खुले आम बेच रहे हैं, जबकि 256 केबीपीएस से कम स्पीड को ब्रॉड बैंण्ड कहा ही नहीं जा सकता। इस तरह आम जनता के साथ कौन फ्रॉड कर रहा है? आपका मंत्रालय, आपका विभाग। यूरोपियन देशों में जहां आज भी 64, 128 एमबीपीएस इंटरनेट की बात कही जा रही है, भारत में अभी भी 16 एमबीपीएस तक ही सोचा जा सकता है। मैं आपको एक मिनट के लिए एनडीए शासन में ले जाना चाहता हूं। आप देखिए, उस समय कितना काम हुआ था और आज आपके कंप्यूटर के युग मे, इन्फोर्मेशन टेक्नॉलॉजी के युग में कितना काम हो रहा है। हॉस्टिंग कंपनियों का मामला आपके सामने आया होगा। यू.एस. में पच्चीस हजार से अधिक हॉस्टिंग कंपनीज हैं और भारत में बमुश्किल बारह सौ कंपनियां होंगी। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो जो बारह सौ कंपनियां हैं, उनका सर्वर यू.एस. में है, भारत में नहीं है, यानी यह सुरक्षा के लिए कितना घातक है। यदि हमारे सभी तरह के डाटा, सरकारी, गैर सरकारी, व्यापारिक से लेकर सुरक्षा तक की संवेदी सूचनाएं यू.एस. के सर्वर पर उपलब्ध है, तब यह हमारी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत घातक है।

आज तक सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई भी ऐसी संस्था नहीं खोली गई है, जो मूल सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए विश्व में विशिष्ट तौर पर कार्य कर रही हो।

यह आपको सोचना होगा। Hosting का काम भारत में हो सकता है, परन्तु आपका मंत्रालय इसे करना नहीं चाहता है और करने नहीं देना चाहता

है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर की बहुत बातें होती हैं। मैं आपको उसकी कहानी सुना देता हूँ। जहाँ तक सॉफ्टवेयर का प्रश्न है, देश ने निजी कम्पनियों के माध्यम से प्रगति की है। हम इसकी सराहना करते हैं। यह सराहनीय है, परन्तु यह प्रगति मूल सॉफ्टवेयर के आधार पर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में है। आज तक सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई भी ऐसी संस्था नहीं खोली गई है, जो मूल सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए विश्व में विशिष्ट तौर पर कार्य कर रही हो। दुर्भाग्य की बात है कि मूल सॉफ्टवेयर अर्थात् सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आपरेटिंग सिस्टम हो, डाटा बेस मैनेजमेंट हो, सिस्टम नेटवर्क हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, यूआरबी हो, इन क्षेत्रों में भारत देश के रूप में हम कहीं भी ऐसा नहीं कहते। उपरोक्त सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक भी सॉफ्टवेयर में भारत का अपने नाम का ब्रांड है ही नहीं।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले दो मोटी–मोटी बातें कहना चाहता हूँ। आप बीएसएनएल की स्थिति देखिए। इसमें 97% की भारी गिरावट आई है। 20 जुलाई 2009 को टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे पास है, बीएसएनएल के निष्पादन पर एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मात्र 2 सालों के भीतर बीएसएनएल के लाभांश में 97 फीसदी की भारी गिरावट आई है। गौरतलब है कि सेना और रेलवे के बाद बीएसएनएल में सर्वाधिक सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। बीएसएनएल का देश के आर्थिक विकास में काफी अहम रोल है, क्योंकि सरकार को हर वर्ष कर व लेवी के रूप में 24 हजार करोड़ से 30 हजार करोड़ रुपए तक इसका योगदान होता है। उपसभापति महोदय, 2008–09 में बीएसएनएल का शुद्ध लाभ मात्र 104 करोड़ रुपए था, जबकि 2007–08 में इसका शुद्ध लाभ 3,009 करोड़ रुपए था, जबकि 2006–07 में बीएसएनएल का शुद्ध लाभ 11,806 करोड़ रुपए था। अब एमटीएनएल पर आ जाइए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुम्बई और दिल्ली में टेलीफोन सेवाएँ मुहैया कराने वाली सार्वजनिक उपक्रम एमटीएनएल का एक तिमाही के दौरान घाटा 83 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एमटीएनएल के खस्ता हाल की असली वजह सरकार की बदइंतजामी है, न कि वैश्विक मंदी। हम कह देते हैं कि वैश्विक मंदी के कारण यह सब हो रहा है। ऐसा नहीं है। एमटीएनएल के पूर्व सीएमडी एस. राजगोपालन का मानना है कि आने वाले वर्षों में एमटीएनएल की तरह बीएसएनएल की स्थिति भी खराब हो जाएगी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, "If we do not free MTNL from the control of the Government, it

is going to be doomed soon. BSNL will also follow the same path and will become ran player in few years."It is given on page 27 of Telecom LIVE June 2009. यह हालात है आपकी दुनिया का और आप कह रहे हैं कि हम भारत को 21वीं सदी में ले जाएंगे। यह धोखा आप न भाजपा को दे रहे हैं, न सांसदों को दे रहे हैं, यह धोखा भारत को है और भारत को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है। अगर आप इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर की दुनिया में गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको अपनी चीजें खड़ी करनी होंगी। मुझे लगता है कि यह विभाग निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देगा। धन्यवाद।

Synopsis

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

SHRI PRABHAT JHA, initiating the discussion, said: Post and Telegraph is a capable medium of cultural, social and economical development in India. Nearly 6 lakh people work in this department. Sometimes, whitewash and painting work is done in the Post Offices in the name of modernization. The number of letters has not reduced even today, but there has been no permanent appointment in the Department of Post and Telegraph since 1984. There are only 5 per cent appointments done on compassionate ground, but no attention is paid to the condition of the rest 95 per cent. The coach labeled 'Department of Post and Telegraph' in the trains is not being added these days. Now, sorting of the letters is also not done. No appointments are done in the place of the people who retire from the department. The work in one department of the Ministry of Communications and Information Technology is still being done manually. The condition of Speed Post is also not good. The officials of Post and Telegraph Department are running private courier service posing as benamis. Gramin Sevak, who are functioning in Postal Department, have to work like regular employees, but they do not get pension and gratuity. The Budget has been reduced for the vans which take letters to the villages. The employees of post offices work in NREGA. According to the report of CAG, the work of Cash Certificates is being done negligently and bungling and corruption in crores is prevalent there. Equal status is not being accorded to all the unions. ACP schemes

should be applicable to all the categories of postal employees, outsourcing should be stopped and action should be taken in the matter of corrupt Government employees. The website of Department of Information Technology has not been updated. There was no mention about information technology in President's Address. Apart from Internet and Broadband, nothing else has been mentioned in the Economic Survey also. Similarly, no other words like information technology can be seen in the Budget Paper. 5666 towers have been installed in rural areas whereas the number of towers in urban areas is more than 4 lakh. The 5 per cent levy for telecommunication development in rural areas is collected under USO and not even 30 per cent of that has been spent by Government in rural areas. This is creating digital divide in India. The Ministry should not behave in this discriminatory manner with the villages. As far as Internet usage is concerned, we are behind even Pakistan. 60 thousand villages do not have even electricity, then what will they do with the computer. The use of computer in our country is not increasing because we have not made any effort regarding languages. If we want to reach the small villages, we will have to take the help of the languages, but the budget allocated in this regard is the same as in the last year. It was announced in Bihar that each call will be charged at 10 paise per minute, but nothing has been done so far in this matter. No work has been done with regard to the announcement of Mobile Number Portability (M.N.P.). Similarly, Voice Over Internal Protocol has also not been implemented till date. The Ministry has given unnecessary exemption to private operators whereas MTNL and BSNL have to compete with them under the rules. All types of data regarding Government, non-government, trading and security related sensitive information is available on American Server. This is very dangerous from our security point of view.

As far as the question of software is concerned, the country has made progress through private companies. We appreciate it. But India is not having its own brand in the field of System Software in the world. BSNL have an important role in the economic development of the country. Its performance has deteriorated. MTNL provides telephone services in Mumbai and Delhi. It is also in bad condition and the reason is poor management by the Government, not the global recession. I hope the Government would certainly take note of it.